समझौता-ज्ञापन (एमओयू)
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

वित्तीय वर्ष/FINANCIAL YEAR 2024-25

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

एवं/AND

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, GOVERNMENT OF INDIA

क्रम Sr. No.	विवरण Particulars	पृष्ठ Page
1.	समझौता-ज्ञापन (एमओयू) 2024-25 MoU 2024-25	1-2
2.	2024-25 हेतु अनुपालन मानदंड Compliance parameters for 2024-25	3-4

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (स्टैंडअलोन) – समझौता-ज्ञापन (एमओयू) 2024-25

क्र.सं.	पैरामीटर	यूनिट	भारिता	लक्ष्य 2024-25
1	प्रचालन से आय	रूपए करोड़ में	8	106.75
2	नये लाभार्थियों की कुल संख्या	संख्या	5	120943
3	पीएम- दक्ष (मंत्रालय योजना) के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	संख्या	5	21600
4	आय प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए	%	10	69.96
5	निवल मूल्य पर लाभ	%	15	2.78
6	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5	3.83
7	कुल उपलब्ध निधियों में से संवितरित ऋण	%	10	100
8	सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को संवितरित ऋण	%	10	53.08
9	कुल ऋण में से अतिदेय ऋण	%	5	0.00
10	कुल ऋण में से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए)	%	5	0.00
11	भौगोलिक विस्तार	%	5	100
12	लक्षित लाभार्थियों को निधियों का संवितरण	%	10	100
13	निर्दिष्ट समय के भीतर TReDS पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के चालान(बिल) की स्वीकृति/ अस्वीकृति	%	5	100
14	अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार GeM से खरीद	%	2	100
		Total	**100**	

टिप्पणी :

- लक्ष्य वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के अनुमानों पर आधारित हैं और ये आधार वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर संशोधन के अधीन होंगे।
- बेंचमार्किंग के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए विजन (VISION) पर भी विचार किया जाता है।
- 50% से 100% लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए आनुपातिक अंक।
- लक्ष्य के 50% से कम उपलब्धि के लिए कोई अंक नहीं ।

National Scheduled Castes Finance & Devp. Corporation (Standalone) – MoU 2024-25				
S.No.	**Name of Parameter**	**Unit**	**Weightage**	**Target 2024-25**
1	Revenue from Operations	Rs. Cr.	8	106.75
2	Total Number of New Beneficiaries	Nos.	5	120943
3	Number of persons trained under PM-DAKSH (Ministry Scheme)	Nos.	5	21600
4	EBTDA as a percentage of Revenue	%	10	69.96
5	Return on Net Worth	%	15	2.78
6	Asset Turnover Ratio	%	5	3.83
7	Loans Disbursed to Total Funds Available	%	10	100
8	Loans Disbursed to Micro Finance beneficiaries	%	10	53.08
9	Overdue Loans to Total Loans	%	5	0.00
10	NPA to Total Loans	%	5	0.00
11	Geographical Coverage	%	5	100
12	Last Mile disbursement to ultimate beneficiaries	%	10	100
13	Acceptance/ Rejection of Invoices of Goods & Services through TReDS Portal within specified time	%	5	100
14	GeM Procurement as per approved procurement plan	%	2	100
		Total	**100**	

Notes:

- The targets are based on projections for the FY 2022-23 and 2023-24 and the same shall be subject to revision on the basis of audited figures of Base year.
- Vision provided by the administrative Ministry is also considered for Benchmarking.
- Proportionate marks for achievement of 50% to 100% Targets.
- No marks for achievement below 50% of Targets.

2024-25 हेतु अनुपालन मानदंड			
क्र.सं.	मानदंड	अंक	स्रोत/सत्यापन
1.	डीपीई द्वारा सीएसआर (CSR) पर सीपीएसईएस (CPSEs) को समय- समय पर जारी किए गए दिशानिर्देश।	-1	प्रशासनिक मंत्रालय
2.	कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियमन) में प्रावधानों का अनुपालन जैसे: (i) निदेशक मंडल का संगठन, (ii) बोर्ड समितियां (लेखापरीक्षा समिति आदि), (iii) बोर्ड बैठकें आयोजित करना, (iv) संबंधित पार्टी लेनदेन, (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता।	-3	प्रशासनिक मंत्रालय के आधार पर सीएजी/सांविधिक/ सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट
3.	परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर नीति आयोग द्वारा दिए गए, लक्ष्य।	-1	नीति आयोग से पुष्टि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा
4.	कुल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के % के रूप में एमएसई के माध्यम से वस्तु और सेवाओं की खरीद – 25%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा
5.	कुल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के % के रूप में अनुसूचित जाति/जनजाति एमएसई के माध्यम से वस्तु और सेवाओं की खरीद - 4%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा
6.	कुल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के % के रूप में महिला एमएसई के माध्यम से वस्तु और सेवाओं की खरीद - 3%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा
7.	सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार की दृष्टि से उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य)	-1	प्रशासनिक मंत्रालय
8.	डीपीई ओएम संख्या डीपीई फिन दिनांक-2007/(4)7- में उल्लिखित ट्रेड्स से संबंधित प्रावधान का 04.05.2020 अनुपालन।	-1	प्रशासनिक मंत्रालय

अप्रनि, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
दिनांक: 28/08/2023

RAJNISH KUMAR JENAW
Chairman-cum-Managing Director, NSFDC
Ministry of Social Justice & Empowerment
Govt. of India

सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिनांक:

सौरभ गर्ग / SAURABH GARG
सचिव / Secretary
भारत सरकार / Govt. of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
नई दिल्ली / New Delhi

System Generated – MoU Dashboa

Compliance parameters for 2024-25			
S.No.	**Parameter**	**Marks**	**Source/ Verification**
1	DPE guidelines issued from time to time on CSR expenditure by CPSEs.	-1	Administrative Ministry
2	Compliance of provisions in the Companies Act, 2013 (or SEBI (LODR) regulations in case of listed entities) on Corporate Governance such as: (i) Composition of Board of Directors (ii) Board Committees (Audit Committee etc.) (iii) Holding Board Meetings (iv) Related Party Transaction (v) Disclosures and Transparency	-3	Administrative Ministry on the basisof CAG/ Statutory/ Secretarial Auditor Report(s)
3	Target as given by NITI Aayog on Assets Monetization Milestones	-1	Administrative Ministry on the basis confirmation from NITI Aayog
4	Procurement of goods or services through MSEs as % of Total procurement of goods and services – 25%	-1	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
5	Procurement of goods or services through SC/ST MSEs as % of Total procurement of goods and services – 4%	-1	Administrative Ministry on the basisof Sambandh portal
6	Procurement of goods or services through Women MSEs as % of Total procurement of goods and services – 3%	-1	Administrative Ministry on the basisof Sambandh portal
7	Steps and initiative taken for Health & Safety improvement of Human Resources in CPSEs (Target to be prescribed by the Administrative Ministry)	-1	Administrative Ministry
8	Compliance with provision relating to TreDS as outlined in DPE OM No.DPE-7(4)/2007-Fin dated 04.05.2020.	-1	Administrative Ministry

CMD, National Scheduled Castes Finance & Development Corporation
Date: 28/08/2023

RAJNISH KUMAR JENAW
Chairman-cum-Managing Director, NSFDC
Ministry of Social Justice & Empowerment
Govt. of India

Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment
Date:

सौरभ गर्ग / SAURABH GARG
सचिव / Secretary
भारत सरकार / Govt. of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
नई दिल्ली / New Delhi

System Generated – MoU Dashboard